BCC BULLETIN
THE BIHAR CHAMBER OF COMMERCE
Vol. XXXXIII | 28th March 2012 | No. 4

एसोचैम व बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से फूड प्रोसेसिंग इन्वेस्टमेंट सम्मिट

आगे बढ़ें उद्यमी : श्री नरेंद्र सिंह, कृषि मंत्री

सम्मिट का दीप प्रज्जवलित कर उद्घाटन करते माननीय कृषि मंत्री श्री नारेन्द्र सिंह, श्री रवि विग, चेयरमैन, बिहार डेवलपमेन्ट काउंसिल एसोचैम माननीया उद्योग मंत्री डॉ॰ रेणु कुमारी कुशवाहा, चैम्बर अध्यक्ष श्री ओ॰पी॰ साह, प्रधान सचिव, उद्योग विभाग श्री सी॰ के॰ मिश्रा

उद्योग लगाने के लिए दृढ़ इच्छाशक्ति का होना अति आवश्यक है। इसके लिए उद्यमी आगे बढ़ें, सरकार ने रास्ता खोल दिया है। 25 फरवरी 2012 को एसोचैम व बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से फूड प्रोसेसिंग इन्वेस्टमेंट सम्मिट में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह ने ये बातें कहीं।

उन्होंने कहा कि फूड प्रोसेसिंग इन्वेस्टमेंट पर यहां चर्चा करने के बजाय उद्योगपतियों व किसानों के बीच जाकर बात करनी होगी। अधिक-से-अधिक लोगों को इसकी जानकारी देनी होगी। किसानों को अपना काम (उत्पादन का) करना होगा और उद्यमियों को अपना। दोनों के बीच सामंजस्य स्थापित होगा और फिर हम आगे बढ़ पायेंगे। उन्होंने कहा कि व्यापारी हमारे रीढ़ हैं। इनके बिना कोई राज्य आगे नहीं बढ़ सकता। उन्होंने स्वदेशी व्यापारियों से आगे आने की भी अपील की और कहा कि ऐसा नहीं होने पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों की गुलामी हमें करनी पड़ेगी।

उद्योग मंत्री रेणु कुमारी ने कहा कि बिहार का कल्याण छोटे उद्योगों से ही संभव है। हर किसान अपने घर के आगे एक छोटा उद्योग लगाएं। इसके लिए यह जरूरी है कि किसानों के बीच जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार ने ऐसा माहौल बनाया है, जिससे कि हम छोटे-छोटे उद्योग आसानी से लगा सकते हैं। बस जरूरत है, प्रखंड व पंचायत स्तर पर प्रशिक्षण की, जिसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि बैंकवालों से असहयोग मिल रहा है, जिसे दूर करने की जरूरत है। सम्मिट के दौरान एक पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन भी दिया गया, जिसके माध्यम से फूड प्रोसेसिंग में संभावनाओं पर विस्तार से प्रकाश डाला गया। इस अवसर पर कौटिल्य ग्रुप के निदेशक सह फूड कंसल्टेंट संजीव श्रीवास्तव, आम्रपाली फूड लिमिटेड के निदेशक सह बीआइए के अध्यक्ष के॰ पी॰ एस॰ केसरी, संजय गांधी इंस्टीच्युट ऑफ डेयरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पटना के डीन डॉ एम॰ एन॰ सिंह, नेचुरल्स डेयरी के एमडी हेमंत कुमार दास, नाबार्ड के असिटेंट मैनेजर राजीव नंदन, विष्णु सी श्रीवास्तव आदि ने भी विचार रखे।

उक्त अवसर पर चैम्बर अध्यक्ष ओ॰ पी॰ साह, चैम्बर उपाध्यक्ष श्री गणेश कुमार खेतड़ीवाल एवं नन्हे कुमार, कोषाध्यक्ष श्री सुबोध कुमार जैन, महामंत्री संजय कुमार खेमका, पूर्व अध्यक्ष युगेश्वर पाण्डेय एवं पी॰ के॰ अग्रवाल उपस्थित थे।

धन्यवाद ज्ञापन एसोचैम के वरीय निदेशक ओम एस॰ त्यागी ने दिया।

वक्ताओं की राय

बिहार में फूड प्रोसेसिंग की अपार संभावनाएं हैं। इसके लिए अब हमारी दिशा होनी चाहिए-चलो गांव की ओर। कृषि आधारित उद्योग लगाने के लिए हमें गावों में जाकर लोगों को प्रेरित व जागरूक करना होगा।

– ***रविविग,चेयरमैन,*** बिहार डेवलपमेंट काउंसिल, ऐसोचैम

एसोचैम उद्यमियों से बिहार में निवेश कराये, नहीं तो इस सम्मिट का कोई मतलब नहीं रह जायेगा। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग बिहार सरकार की प्राथमिकता में है। इसमें अपार संभावनाएं हैं।

– ***ओ॰पी॰साह,*** अध्यक्ष, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स

उद्योग के लिए अच्छा माहौल बना है, लेकिन उस अनुपात में यह लग नहीं पा रहा है। इसके लिए हैंड होल्डिंग सपोर्ट की आवश्यकता है। सरकार बैंकों के प्रति भी प्रभावी कदम उठाये, ताकि किसी को लोन के लिए दौड़ना नहीं पड़े।

– ***डी०के०सिंह***,निदेशक, एमएसएमइ इंस्टीट्यूट

खाद्य प्रसंस्करण के साथ बिजली के क्षेत्र में भी राज्य में अपार संभावनाएं है। इसमें निवेश कर उद्यमी बहुत-कुछ पा सकते है। एसोचैम की भी गाँव के लिए की गयी परिकल्पना सिर्फ कागज पर ही दिखती है।

– ***सी०के०मिश्रा***,प्रधान सचिव, उद्योग विभाग

नौजवानों को नौकरी के बजाय स्वरोजगार के लिए सोचना चाहिए। फूड प्रासेसिंग के क्षेत्र में युवा काफी अच्छा कर सकते हैं। बस उनमें दृढ़ इच्छाशक्ति होनी चाहिए। इसके लिए राज्य सरकार को प्रखंड व पंचायत स्तर पर प्रशिक्षण देना चाहिए।

– ***अजितकुमार***, संयुक्त सचिव, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज मंत्रालय, भारत सरकार

बिहार सरकार फूड प्रोसेसिंग के संबंध में काफी अच्छा काम कर रही है। इसलिए लोगों को इसमें बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। यहां कॉटेज लेवल इंडस्ट्री की अपार संभावनाएं हैं।

– ***डॉके०ए०सुंदरम***,निदेशक, आइआइसीपीटी

(साभार:प्रभातखबर26.02.2012)

NEED FOR COORDINATION AMONG TAX PAYERS AND TAX COLLECTORS

Shri S. T. Ahmad, CIT-1 addressing the programme (extreme right). Seating on his right are Shri Vijay Sharma, CCIT-I, Shri O. P. Sah, President, Shri P. K. Agrawal, Former President and Shri G. K. Khetriwal, Vice President.

Chief Commissioner of Income Tax-1 Vijay Sharma on Monday, 5th March 2012 said that though Bihar had registered development, the growth is not being reflected by way of a concomitant increase in the collection of direct taxes, as was the case in similarly positioned states.

Speaking as the chief guest at an awareness programme on advance tax, organised at Bihar Chamber of Commerce, Sharma said, "while global economic crisis has impacted revenue collection in metropolitan cities, several states, like MP, Chattishgarh and Rajasthan have emerged as the new centres of growth along with Bihar. But while the IT collections have been better in these states, things have not turned out the same way here." He opined there was an urgent need for a greater coordination among the tax payers and tax collectors to shore up direct taxes to central pool, which, in turn, could be ploughed back for the development of the state. "While this would provide a sense of pride and participation in growth, it would also inculcate a feeling of ownership among the stakeholders. Once the stakes are high, it also encourages people to question why development and welfare activities are not being taken up," he explained.

Emphasizing the need for reflection of economic growth in tax collection figures, Sharma said, "We have almost come to the end of the current fiscal. It is now time to clear liability, particularly advance tax, latest by March 15. Self-assesses should pay advance tax by arriving at a ratio in comparison to the tax payment last year, as we are depending on advance tax collection."

He said the BCC members should not only think of their responsibility but also cooperate in motivating new taxpayers to join the pool of assesses. "They should take upon themselves the task of clearing arrear demands and ensuring greater and effective compliance of tax deduction at source in view of the all-around growth in the state in the areas of trade, small industries, services, infra-structure (road and building) and agriculture," he said. The CCIT-1 also announced that the depart-ment would set up an IT Service Centre to provide assistance to taxpayers. "While we are trying to expedite the processing time for paper returns to ensure faster refunds, we urge taxpayers to file IT returns online for quick and timely refunds," he said, adding "anybody, having a problem, is welcome to approach us. We are open to suggestions."

He also accepted the suggestions for holding regular grievance redressal camps saying that the first grievance redressal fortnight would be held in April. "Grievances would be taken up on a priority basis. And in the event of any grievance, an assesses should meet the next level officer instead of going downwards in the hierarchy," he said.

Earlier, CIT-IST Ahmad also highlighted the need for making up the shortfall in tax collection during the first three quarters in the last quarter saying "We have found that assesses were not paying advance tax. While notice have been sent with specific tax liability, corporates should work out their tax liability and pay accordingly"

BCC President OP Sah welcomed the guests, while Former BCC President and Chairman of Taxation Committee, P. K. Agarwal placed the expectations and suggestions on behalf of the members. R. Manjunath Swamy, Alok Kumar and R. K. Chaudhary, all Income Tax Officials, Jugeshwar Pandey, Former BCC President, G. K. Khetriwal and Nanhey Kumar, Vice Presidents BCC, Hony. Treasurer Subodh Kr. Jain and tax consultants, chartered accountants and assesses were also present.

(Source : H.T. 6.3.2012)

उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन में चीन अव्वल

चीनी युवा प्रतिनिधियों का चैम्बर में स्वागत

कृषि उपभोक्ता वस्तुओं के साथ चीन चावल के उत्पादन में विश्व में सबसे आगे है। इसके साथ ही आलू, गेहूं, मकई, तंबाकू, सोयाबीन व चाय की पैदावार भी चीन में अच्छी है। उक्त बातें बिहार चैम्बर ऑफ कामर्स के अध्यक्ष ओ० पी० साह ने 29 फरवरी 2012 को कहीं। वे बिहार चैम्बर ऑफ कामर्स में महामहिम गुआन वेई, सचिव, सेंट्रल कमीटी ऑफ द कम्युनिस्ट यूथ लीग ऑफ चायना के नेतृत्व में बिहार आये चीनी युवा प्रतिनिधमंडल के साथ बैठक को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए कहा कि चीन 1.3 बिलियन अबादी के साथ विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश तो है ही, यह चावल, कृषि और

उपभोक्ता उत्पाद बनाने के मामले में भी अग्रणी है।

उन्होंने प्रतिनिधिमंडल को बोधगया, भगवान बुद्ध, गया स्थित महाबोधि मंदिर, महाबोधि वृक्ष, राजगीर के बारे में विस्तार से जानकारी दी। नालंदा विश्व-विद्यालय की महत्ता पर भी उन्होंने प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि यहाँ से बौद्ध धर्म किस तरह से दुनिया भर में फैला। वर्त्तमान में इस विश्वविद्यालय को बिहार सरकार किस तरह से नया रूप प्रदान करने में जुटी है। चीनी प्रतिनिधिमंडल में छात्र, व्यवसायी सहित कई अधिकारी शामिल थे। बिहार आए प्रतिनिधिमंडल में 67 लोग थे। यह युवा प्रतिनिधिमंडल बिहार के विकास से काफी प्रभावित थे। भगवान बुद्ध और उनसे जुड़े तथ्यों का अवलोकन करने के साथ ही प्रतिनिधिमंडल बिहार के महत्वपूर्ण स्थलों व संस्थाओं का भी भ्रमण करेंगे। चीनी प्रतिनिधिमंडल ने चैम्बर द्वारा किये गये आतिथ्य हेतु आभार व्यक्त किया। चैम्बर अध्यक्ष ने श्री गुआन वेई को स्मृति चिह्न भी भेंट किया। इस अवसर पर चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष पी. के. अग्रवाल, उपाध्यक्ष नन्हे कुमार, कोषाध्यक्ष सुबोध कुमार जैन, पूर्व अध्यक्ष के. पी. सिंह एवं टी.बी.एस. जैन सहित चैम्बर के सदस्य काफी संख्या में उपस्थित थे। धन्यवाद ज्ञापन उपाध्यक्ष श्री जी. के. खेतड़ीवाल ने किया।

चीनीप्रतिनिधिमंडलकास्वागतसंबोधनकरतेचैम्बरअध्यक्षश्रीओ०पी०साह।उनकीबायींओरमहामहिमगुआनवेईएवंचैम्बरउपाध्यक्ष श्रीजी०के०खेतड़ीवाल।दायींओरक्रमशः:चीनीइण्टरप्रेटर,पूर्वअध्यक्षश्रीपी०के०अग्रवाल,पूर्वउपाध्यक्षश्रीटी०बी०एस०जैनएवं पूर्वउपाध्यक्षश्रीके०पी०सिंह।

प्रतिनिधिमंडलकेसदस्यगण

(साभार:दैनिकजागरण:1/3/2012)

चैम्बर में होली मिलन समारोह

होलीमिलनसमारोहमेंमाननीयकृषिमंत्रीश्रीनरेन्द्रसिंहकास्वागतकरतेचैम्बरअध्यक्षश्रीओ.पी.साह। साथमेंपूर्वअध्यक्षश्रीमोतीलालखेतानएवंश्रीविशालटेकरीवाल।

समारोहमेंहोलीगीतप्रस्तुतकरतेकलाकारइन्द्रजीतगांगूलीएवंबंदानीगांगूलीएवंअन्य

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स में 4 मार्च 2012 (रविवार) को होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में राज्य सरकार में मंत्री, विधायक, अधिकारी सहित कई व्यापारी एवं उद्योगपति शामिल हुए।

समारोह में भाग लेने वाले लोगों ने अबीर व गुलाल लगाकर एक दूसरे को होली की बधाई दी। समारोह में आने वाले अतिथियों को चैम्बर के अध्यक्ष ओ. पी. साह सहित अन्य सदस्य अबीर-गुलाल लगाकर स्वागत कर रहे थे। समारोह में कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह, पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव, खाद्य-आपूर्ति मंत्री श्याम रजक, जिलाधिकारी संजय कुमार एवं दैनिक जागरण के मुख्य महाप्रबंधक आनंद त्रिपाठी सहित कई लोग समारोह में शामिल होकर चैम्बर के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों को होली की बधाई दी।

कलाकार इन्द्रजीत गांगुली एवं बंदानी गांगुली ने होली गीतों से लोगों को खूब झुमाया। मौके पर उन्होंने गाया-मेरा कान्हा मधुबन में खेले होली। समारोह में चाट, गोलगप्पा, कुल्फी व मिठाई का दौर चलता रहा। समारोह को सफल बनाने में चैम्बर के महासचिव संजय खेमका, पूर्व महासचिव पशुपति नाथ पाण्डेय, पूर्व कोषाध्यक्ष गोविन्द कानोडिया, उपाध्यक्ष गणेश खेतड़ीवाल, जदयू व्यावसायिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष अमर कुमार अग्रवाल, शशि मोहन, नंद किशोर अग्रवाल एवं युगल किशोर चौधरी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी।

समारोह में चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष युगेश्वर पाण्डेय, पी. के. अग्रवाल, डी. पी. लोहिया, मोतीलाल खेतान, पूर्व उपाध्यक्ष के. पी. सिंह, सुरेश प्रकाश गुप्ता, पूर्व महामंत्री एन. के. ठाकुर सहित चैम्बर के काफी सदस्य अपने परिवार सहित उपस्थित थे।

(साभार:दैनिकजागरण,05.02.2012)

आम बजट – 2012-13 की खास बातें

सभी की नजर इस वर्ष के आम बजट को लेकर वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी की घोषणाओं पर टिकी रही। पूंजी बाजार, वित्तीय संस्थान और निवेशकों में से सभी को बजट से कुछ न कुछ मिलने की उम्मीद थी। कुछ के लिए यह ठीक है, लेकिन सभी खुश नहीं हैं।

- ढांचागत क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय संस्थानों को वित्त वर्ष 2012-13 में करमुक्त बॉन्ड जारी कर 60,000 करोड़ रुपये जुटाने की अनुमति दी गई है। 2011-12 के लिए ढांचागत परियोजनाओं के वित्त पोषण के वास्ते करमुक्त बॉन्ड के जरिए 30,000 करोड़ रुपये जुटाने की छूट दी गई थी।
- कृषि क्षेत्र में ऋण की उपलब्धता सरल बनाने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (केसीएस) को स्मार्ट कार्ड में तब्दील किया जाएगा जिसका इस्तेमाल एटीएम कार्ड के तौर पर किया जा सकेगा। किसानों को कृषि ऋण उपलब्ध कराने के लिए एक प्रभावी माध्यम है।
- प्रस्तावित प्रत्यक्ष कर संहिता की तर्ज पर सरकार ने सेवा कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क के लिए समान कर संहिता (सीटीसी) लाने की योजना बनाई है, ताकि इन दोनों अप्रत्यक्ष करों को तर्कसंगत बनाया जा सके।
- बजट में कमजोर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पूंजीकरण की योजना को अगले दो साल के लिए बढ़ाने का प्रस्ताव किया है ताकि सभी राज्य इसमें अपना योगदान दे सकें। मुखर्जी ने कहा कि सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर 40 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पूंजीकरण की प्रक्रिया शुरू की है और फरवरी 2012 तक इनमें से 12 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का काम पूरा हो गया है।
- बैंकिंग सुविधाएं बढ़ाने के लिए स्वाभिमान अभियान के विस्तार का प्रस्ताव किया। दो हजार से ज्यादा आबादी वाली बस्तियों में बैंकिंग सुविधाएं बढ़ाने के लिए 2010-11 में 'स्वाभिमान' अभियान शुरू किया गया था।
- सरकार ने अति लघु एंव मझोले उद्यमों के लिए इक्विटी पूंजी की उपलब्धता बढ़ाने के लिए सिडबी के साथ 5,000 करोड़ का वेंचर स्थापित करने का प्रस्ताव किया है।
- बजट सत्र में 'पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण विधेयक 2011', बैंकिंग विधि (संशोधन) विधेयक, 2011 और बीमा विधि (संशोधन) विधेयक, 2008 मं संशोधन लाया जाएगा।
- कौशल विकास के लिए संस्थागत कर्ज का प्रवाह मजबूत करने के लिए अलग से एक क्रेडिट गारंटी फंड बनाया जाएगा। इससे युवाओं को बाजरोन्मुखी कुलशता का विकास करने में मदद मिलेगी।

बजट में दवा क्षेत्र के लिए शोध और विकास व्यय में 200 फीसदी वेटेड कटौती की एक बड़ी घोषणा की गई: लेकिन उसमें क्षेत्र के लिए कुछ खास नहीं रहा। भारतीय दवा उद्योग का अनुमानित कारोबार 9 अरब डॉलर है और इस वजह से दुनिया का चौथा बड़ा बाजार है।

- सर्व शिक्षा अभियान के लिए 2012-13 के बजट अनुमान में 25,555 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए गए जो 2011-12 के मुकाबले 21.7 फीसदी अधिक है।
- मौजूदा पोलियो टीका इकाइयों का आधुनिकीकरण होगा और चेन्नई के पास एकीकृत टीका इकाई की स्थापना होगी। एनआरएचएम के लिए वर्ष 2011-2012 में आवंटित 18,115 करोड़ रुपये की राशि को बढ़ाकर 20,882 करोड़ रुपये किया गया। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत की जा रही है।
- घरेलू विमानन कंपनियों में विदेशी एयरलाइंस को 49 फीसदी तक की भागीदारी अनुमति का प्रस्ताव।
- हाइब्रिड या इलेक्ट्रिल वाहनों के बैटरी पैकों के विनिर्माण के लिए कुछ मदों पर बुनियादी सीमा शुल्क और विशेष सीवीडी से रियायत बढ़ाई जा रही है। बड़ी कारों, एमयूवी-एमयूवी की पूरी तरह निर्मित इकाइयों की कुछ श्रेणियों के लिए बुनियादी सीमा शुल्क बढ़ाने का प्रस्ताव।
- बिजली उत्पादन के लिए बुनियादी शुल्क से पूरी छूट, कोयला खनन परियोजना के लिए बुनियादी सीमा शुल्क से पूरी छूट, खनिजों के सर्वेक्षण और संभावना के लिए जरूरी मशीनरी और उपकरणों के लिए बुनियादी सीमा शुल्क कम करने का प्रस्ताव।
- प्रोबायोटिक्स पर बुनियादी सीमा शुल्क घटाने, ऊर्जा बचत उपकरणों, और तापीय परियोजनाओं के लिए आवश्यक संयंत्र और उपस्करों के लिए छूट का प्रस्ताव।
- रेलवे सुरक्षा और चेतावनी प्रणाली की संस्थापना और तीव्र गति की रेल गाड़ियों के लिए ट्रैक संरचना के उन्नयन में आवश्यक उपस्करों के लिए बुनियादी सीमा शुल्क के घटाने के प्रस्ताव।
- सड़क निर्माण के लिए जरूरी विशिष्ट उपकरणों की कुछ श्रेणियों, सुरंग खोदने वाली मशीनों और उनके पूर्जों पर आयात शुल्क में छूट।
- इस्पात, वस्त्र उद्योग, ब्रांडेड तैयार परिधान, किफायती चिकित्सा उपकरण, आम उपयोग की चीजें तैयार करने वाले श्रम प्रधान क्षेत्र और अर्ध यांत्रिक इकाइयों द्वारा बनाई जाने वाली दियासलाई जैसे क्षेत्रों को राहत।
- सरकार बहु-ब्रांड खुदरा व्यापार में 51 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देने के निर्णय के संबंध में राज्य सरकारों के साथ विचार-विमर्श कर सहमति बनाने की कोशिश करेगी।
- एनएचडीपी के तहत 8,800 किलोमीटर सड़क परियोजनाओं को लाने का प्रस्ताव। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का आवंटन 14 फीसदी बढ़कर 25,360 करोड़ रुपये हुआ।
- कोल इंडिया को बिजली कंपनियों के साथ ईंधन आपूर्ति करार करने की सलाह दी गई, जिनके नहीं होने से कई परियोजनओं का विकास बाधित है।

बजट में बुनकरों को वित्त मंत्री की तरफ से तोहफा मिला है। कर्ज माफी के साथ-साथ पावरलूम व दूसरी मशीनों के आयात पर शुल्क में कटौती की गई है इसके अलावा कपड़ा क्षेत्र में ब्रांडेड परिधान पर भी उत्पाद शुल्क में पहले के मुकाबले थोड़ी राहत दी गई है।

- डेयरी क्षेत्र में उत्पादकता सुधारने के लिए विश्व बैंक के सहयोग से 2,242 करोड़ रुपये की परियोजना शुरू करने का ऐलान। सरकार ने प्रोटीन सप्लीमेंट के लिए मिशन को मजबूत करने का लक्ष्य रखा है।
- ताजे जल में मछली पालन के अलावा तटीय क्षेत्रों में मछली उत्पादन बढ़ाने के लिए 2012-13 में आवंटन बढ़ाकर 500 करोड़ रुपये कर दिया गया।
- खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए अगले वित्त वर्ष में राज्य सरकारों के सहयोग से खाद्य प्रसंस्करण पर राष्ट्रीय मिशन का प्रस्ताव।
- मिशन के तहत जहां राज्य सरकारें व्यापक स्तर पर खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित करेंगी, वही केंद्र उन्हें प्रौद्योगिकी व लॉजिस्टिक मदद उपलब्ध कराएगा।
- बिजली क्षेत्र के लिए कर-अवकाश को एक साल और 31 मार्च, 2012 तक के लिए बढ़ाने की घोषणा की गई है। इससे अल्ट्रा मेगा बिजली परियोजनाओं को लाभ मिलेगा।
- इलेक्ट्रिकल स्टील के विनिर्माण के लिए कोटिंग मिनरल और निकल अयस्क पर बीसीडी को 7.5 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया है। वहीं, गैर अलॉय इस्पात उत्पादों पर बीसीडी को 5 फीसदी से बढ़ाकर 7.5 फीसदी किया गया है। क्रोमियम अयस्क पर निर्यात शुल्क को 3,000 रुपये प्रति टन से बढ़ाकर 30 फीसदी यथामूल्य (एडवेलोरम) कर दिया गया है।
- टीसीएस के प्रावधानों को कोयले, लिग्नाइट और लौह अयस्क के कारोबार पर 1 जुलाई 2012 से लागू किया जा रहा है। इसकी निर्धारित दर बिक्री मूल्य की 1 फीसदी है। अगर खरीदार यह घोषणा करता है कि इन खनिजों का इस्तेमाल विनिर्माण, प्रसंस्करण या वस्तुओं के उत्पादन में होगा तो यह कानून लागू नहीं होगा।
- खाद्यान्न भंडारण की समस्या से निपटने लिए 19 राज्यों में 1.5 करोड़ टन अतिरिक्त भंडारण की व्यवस्था की जा रही है। नए भंडार गृह बनाने में निजी उद्यमियों की मदद ली जा रही है। बजट प्रस्ताव में कहा गया है - निजी उद्यम गारंटी योजना के तहत लगभग 1.5 करोड़ टन क्षमता विकसित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित अतिरिक्त भंडारण क्षमता में से लगभग 30 लाख टन 2011-12 के अंत तक तैयार हो जाएगी जबकि 50 लाख टन क्षमता अगले साल बनेगी।

- सरकार ने खनन सर्वेक्षण आदि के काम आने वाली मशीनरी व उपकरणों पर मूल सीमा शुल्क को घटाकर 2.5 फीसदी करने का प्रस्ताव किया है। 2012-13 के बजट प्रस्तावों में वित्त मंत्री ने कहा, "मैं सर्वेक्षण या प्रोस्पेक्टिंग के लिए मशीनरी व उपकरण आदि पर मूल सीमा शुल्क को 10 फीसदी या 7.5 फीसदी से घटाकर 2.5 फीसदी करने का प्रस्ताव करता हूँ।"
- हाथ से बनी बीडियों पर बुनियादी उत्पाद शुल्क 8 से 10 रुपये प्रति हजार करने का प्रस्ताव है

(बिजनेसस्टैंडर्ड:17.3.2012)

केन्द्रीय बजट में बिहार की उपेक्षा–चैम्बर

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने माननीय केन्द्रीय वित्त मंत्री द्वारा 16 मार्च 2012 को संसद में पेश आम बजट में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिये जाने एवं आधारभूत संरचना विकास के लिए बजटीय प्रावधान नहीं किए जाने पर निराशा व्यक्त की है। राज्य की आम जनता विशेष कर उद्योग एवं व्यवसाय से जुड़े लोग इस बजट में बिहार के लिए किसी बजटीय घोषणा का बेसब्री से इन्तजार कर रहे थे।

चैम्बर अध्यक्ष श्री ओ० पी० साह ने कहा कि बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा के संबंध में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा अर्न्तमंत्रालयी समूह के गठन और समूह द्वारा उस पर विचार किए जाने से बिहारवासी काफी आशान्वित थे कि उनकी मांग पूरी होगी।

उन्होंने आन्ध्र प्रदेश एवं झारखंड में दो नये मेगा हथकरघा कलस्टर की अनुमति पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि बिहार को भी इस प्रकार की योजनाएं प्रदान की जानी चाहिए।

उन्होंने मिजोरम, नागालैण्ड एवं झारखंड में बुनकर सर्विस सेन्टर दिए जाने पर निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि इसमें बिहार की अनदेखी की गयी है।

श्री साह ने आयकर की छूट सीमा में बढ़ोत्तरी का स्वागत करते हुए माननीय केन्द्रीय वित्त मंत्री से अनुरोध किया है कि आयकर की छूट सीमा को कम-से-कम तीन लाख रुपया किया जाए जिसकी अनुशंसा संसद की स्थायी समिति ने भी की है। उन्होंने टैक्स ऑडिट की सीमा को 60 लाख से 1 करोड़ किए जाने का भी स्वागत करते हुए कहा कि इससे छोटे व्यवसायियों को राहत मिलेगी।

श्री साह ने सरकारी विभागों द्वारा छोटे एवं मंझोले उद्योगों से 20% अपनी आवश्यकतानुसार खरीद के निर्णय का स्वागत किया है। उन्होंने ताप विद्युत घरों के लिए स्टीम कोयला आयात पर सीमा शुल्क समाप्त किए जाने का स्वागत करते हुए कहा कि इससे विद्युत उत्पादन की लागत में कमी आएगी जिसके फलस्वरूप उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी।

उन्होंने 12वीं पंचवर्षीय में आधारभूत संरचना के विकास हेतु 50 लाख करोड़ का प्रावधान किए जाने जिसमें आधी निवेश राशि निजी क्षेत्र के लिए जाने का भी स्वागत किया है।

उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के तहत 8800 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास किए जाने का स्वागत किया है।

उन्होंने बेसिक एक्साइज ड्यूटी को बढ़ाकर 10% से 12% किए जाने एवं सर्विस टैक्स में 2% की वृद्धि पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि इससे मुद्रास्फीति और बढ़ेगी तथा औद्योगिक क्षेत्र जो कि अभी मंदी के दौर से गुजर रहा है, उसके समक्ष और कठिनाइयाँ आएंगी।

उन्होंने मल्टी ब्रांड रिटेल में 51% विदेशी पूंजी निवेश की मंजूरी का विरोध करते हुए कहा कि इससे छोटे व्यवसायी जो स्वनियोजित हैं, उनके सामने बेकारी की समस्या उत्पन्न होगी।

रेल बजट 2012-13 की खास बातें

• यात्री किराए में दो पैसे से लेकर 30 पैसे प्रति किलोमीटर तक की बढ़ोतरी। • रेलवे दर-सूची नियामक प्राधिकरण बनाने पर विचार। • न्यूनतम किराया और प्लेटफार्म टिकट अब पांच रुपए का। • 75 नई एक्सप्रेस गाड़ियां शुरू की जाएंगी। • 39 गाड़ियों का विस्तार होगा और 23 गाड़ियों के फेरे बढ़ेंगे। • मुंबई उपनगर में 75 अतिरिक्त गॉड़ियां, चेन्नई क्षेत्र में 18 और कोलकाता क्षेत्र में 44 नई उपनगरीय गाड़ियां चलाई जाएंगी। • कोलकाता मेट्रो में 2012-13 के दौरान 50 नई गाड़ियां चलाई जाएंगी। • अर्जुन पुरस्कार विजेताओं को राजधानी और शताब्दी में भी यात्रा सुविधा। • 'इज्जत योजना' के तहत यात्रा दूरी 100 से बढ़ा कर 150 किलोमीटर की गई। • रेलवे में खेलों के लिए एक कार्ययोजना विकसित होगी। • रेलवे हर साल 10 खिलाड़ियों को 'रेल खेल रत्न' पुरस्कार देगा। • रेलवे में 2012-13 के दौरान एक लाख नियुक्तियां होंगी। • रेलवे में अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के खाली पदों को भरा जाएगा। • पहचान किए गए सभी 202 स्टेशनों पर एकीकृत सुरक्षा प्रणाली की स्थापना 2012-13 में पूरी होगी। • रेलवे सुरक्षा बल और राजकीय रेलवे पुलिस अब 3500 ट्रेनों को मार्ग सुरक्षा देगी। • रेलवे सुरक्षा बल की हेल्पलाइन को अखिल भारतीय यात्री हेल्पलाइन के साथ जोड़ा जाएगा। • वर्ष 2012-13 में 102 करोड़ 50 लाख टन माल ढुलाई का लक्ष्य। • यात्री परिवहन बढ़ोतरी 5.4 फीसद, सकल यातायात राजस्व प्राप्ति 132,552 करोड़ रुपए रहने का अनुमान। इस वर्ष के संशोधित अनुमान से 27.6 फीसद बढ़ोतरी। • रेलवे लाभांश भुगतान 6676 करोड़ रुपए रहने का अनुमान। • वर्ष 2012-13 में 725 किलोमीटर नई रेल लाइन के लिए 6872 करोड़ रुपए, 700 किलोमीटर लाइन के दोहरीकरण को 3393 करोड़ 800 किलोमीटर अमान परिवर्तन के लिए 1,950 करोड़ रुपए और 1100 किलोमीटर विद्युतीकरण के लिए 828 करोड़ रुपए का प्रावधान। • 2012-13 के लिए रेलवे की अब तक की सार्वधिक 60100 करोड़ की योजना। • रेलवे स्टेशनों और गाड़ियों में साफ-सफाई के लिए विशेष रख-रखाव संस्था बनाई जाएगी। • पेंट्री कारों और मुख्य रसोई के लिए जानी-मानी पेशेवर एजेंसी की सेवाएं ली जाएंगी। • यात्रियों को एसएमएस और इंटरनेट के जरिए गाड़ियों के चलने की सूचना के लिए ट्रेन सूचना प्रणाली शुरू होगी। • 929 स्टेशनों को उन्नत किया जाएगा। • सिक्का, करेंसी से संचालित टिकट वेंडिंग मशीनें लगाई जाएंगी। • तमिलनाडु में पालुर और महाराष्ट्र में अंबरनाथ में रेलनीर का नया संयंत्र लगेगा। • ई- टिकट के मामले में यात्री के मोबाइल फोन पर एसएमएस को वैध आरक्षण का सबूत माना जाएगा। • महत्वपूर्ण स्टेशनों पर 321 एस्केलेटर्स लगाए जाएंगे। • ढाई हजार रेलडिब्बों में हरति शौचालय लगाए जाएगे। • उत्तरी बंगाल के घने जंगलों से होकर गुजरने वाली 'हरित रेल' चलाई जाएगी। • रायपुर और टोंडियारपुर में दो जैव डीजल संयंत्र को चालू किया जाएगा। • पल्लकड़ में केरल सरकार के सहयोग से रेलकोच फक्ट्री स्थापित होगी। गुजरात के कच्छ और कर्नाटक में कोलर क्षेत्र में राज्य सरकार की सक्रिय भागीदारी से कोच निर्माण की दो अतिरिक्त इकाइयां स्थापित होंगी। • ओड़िशा के गंजम जिले के सीतापली में माल डिब्बा कारखाना स्थापित होगा। • अगरतला से बांग्लादेश के अखौरा से जोड़ने वाली परियोजना अगले वित्त वर्ष में शुरू की जाएगी। • नेपाल के साथ संपर्क बढ़ाने के लिए जोगबनी विराटनगर और जयनगर बिजलपुरा-बरडीबस नई लाइन निर्माण का कार्य प्रगति पर।

(साभार:जनसत्ता,15.03.2012)

बिहार को मिलीं 11 नई गाड़ियां

• छपरा से मंडुआडीह के लिए इंटरसिटी (दैनिक) • सिंकदराबाद-दरभंगा एक्सप्रेस (सप्ताह में दो दिन) • हावड़ा-रक्सौल-एक्सप्रेस वाया आसनसोल-बरौनी (हफ्ते में दो दिन) • कोलकाता-जयनगर एक्सप्रेस वाया आसनसोल-बरौनी (साप्ताहिक) • छपरा-लखनऊ एक्सप्रेस वाया मशरख, थावे (सप्ताह में तीन दिन) • दरभंगा-अजमेर एक्सप्रेस वाया रक्सौल, बरेली, मथूरा (साप्ताहिक) • कामख्या-लोकमान्य तिलक एसी एक्सप्रेस वाया कटिहार मुगलसराय, इटारसी (साप्ताहिक) • हावड़ा-लालकुआं एक्प्रेस वाया मुगलसराय, वाराणसी, लखनऊ (साप्ताहिक) • **पटना से विलासपुर के लिए नयी वातानुकूलित ट्रेन चलेगी • सिखों के दो प्रमुख तीर्थ स्थलों को मिलाने के लिए पटना साहिब-अमृतसर नांदेड एक्सप्रेस ट्रेन चलाने की घोषणा • दैनिक सवारी गाड़ी गोरखपुर-सीवान पैसेंजर।**

5 गाड़ियों को मिला विस्तार

1. मडुआडीह-बापूधाम मोतिहारी एक्सप्रेस को मुजफ्फरपुर तक, 2.वलसाड़-सोनुपर एक्सप्रेस को मुजफ्फरपुर तक,3. पटना-मथुरा एक्सप्रेस को कोटा तक,4. सूरत-वाराणसी एक्सप्रेस को छपरा तक, 5. कोलकाता-दरभंगा एक्सप्रेस को सीतामढ़ी तक

6 नई लाइनों को पूरा करने का लक्ष्य

1. बांका-काकावाड़ा, 2. दानापुर-पाटलिपुत्र (पार्ट), 3. दनियावा-चंडी, 4. रुन्नीसैदपुर-जुब्बा सहनी, 5. महाराजगंज-विष्णुपुर-महुआरी रेल लाइन 6. दनियांवा-छितौनी

11 आदर्श रेलवे स्टेशन बनेंगे

बेगुसराय, फारबिसगंज, घोड़ासहन, नवादा जीरादेई, जोगबनी, लालगंज, गोपालगंज, सुपौल ठाकुरगंज व वारिसलीगंज

आमान परिवर्तन

1. बनमनखी-पूर्णिया 2. सहरसा-सरायगढ़ 3. थावे-छपरा

(साभार:राष्ट्रीयसहारा,15.03.2012)

रेल बजट में बिहार के साथ सौतेलापन - चैम्बर अध्यक्ष

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने संसद में 14 मार्च 2012 को पेश रेल-बजट 2012-2013 पर बिहार के साथ किये गये सौतेला व्यवहार पर गहरी निराशा व्यक्त की है। इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए चैम्बर अध्यक्ष श्री ओ० पी० साह ने कहा कि इस रेल बजट में बिहार की घोर उपेक्षा की गयी है, जो गंभीर चिंता का विषय है।

चैम्बर अध्यक्ष श्री ओ० पी साह ने कहा कि रेल बजट में बिहार में चल रही कुछ प्रमुख रेल परियोजनाओं के शीघ्र पूरा करने के लिए कोई महत्व नहीं दिया गया है जिससे निम्नांकित परियोजनाओं के भविष्य पर गहरी आशंका हो रही है :-

1. पटना और मुंगेर के बीच गंगा पर मेगापुल 2. कोसी पुल 3. मधेपूरा में ग्रीन फिल्ड इलेक्ट्रीक लोको निर्माण ईकाई 4. डालमियॉनगर की रेल बौगी कारखाना 5. सोनपुर में नयी डेमू शेड 6. गड़हरा में वैगन कारखाना 7. समस्तीपुर में कारखाना एवं लोको शेड का विस्तार 8. गड़खा में वैगन पुनर्निर्माण कारखाना 9. जमालपुर में कारखाना

उन्होंने आगे कहा कि इस बात का भय है कि वर्तमान में वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रही रेलवे कहीं इन आवश्यक परियोजनाओं को बन्द या ठंढे बस्ते में न डाल दे। यदि ऐसा हुआ तो यह बिहार के लिए अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण होगा तथा बिहार के प्रति केन्द्र के भेदभाव पूर्ण नीति को स्थापित करेगा।

चैम्बर अध्यक्ष ने सूचित किया कि रेल बजट के पूर्व ही रेल मंत्रालय ने मालभाड़े में लगभग 22% की बढ़ोत्तरी कर दी है जो दिनांक 6 मार्च, 2012 से लागू भी कर दी गयी है। परोक्ष रूप से की गयी इस भारी वृद्धि का कुप्रभाव पूरे देश की आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा और महंगाई और भी बढ़ेगी। माल भाड़े में की गयी इस भारी वृद्धि का सबसे अधिक खामियाजा बिहार सरीखे राज्यों पर पड़ेगा जो अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने की जद्दो-जहद में लगे हैं। उन्होंने आगे कहा कि यद्यपि रेल मंत्री ने अपने बजट भाषण में यात्री किराये में वृद्धि करने के प्रस्ताव को रखते समय कई वर्षों से यात्री भाड़ा न बढ़ाने के फलस्वरूप माल भाड़े में की गयी अप्रत्याशित वृद्धि का जिक्र तो जरूर किया परन्तु उन्होंने इस क्रास सबसीडी को समाप्त करने हेतु न तो कोई फॉर्मूला दिया न ही कुछ कहा।

उन्होंने कहा कि इस रेल बजट में एक बार फिर बिहार को कोई विश्वस्तरीय स्टेशन यहाँ तक की राजधानी पटना को भी वंचित रखा। रेल बजट में बिहार को लगभग नगण्य या काफी थोड़ा ध्यान प्रस्तावित आमान परिवर्तन, रेल लाईन का दोहरीकरण एवं तीसरी रेल लाइन आदि पर दिया गया है।

चैम्बर अध्यक्ष ने कहा कि बिहार के A-1 तथा A क्लास के रेलवे स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं में पर्याप्त बढ़ोत्तरी की नितान्त आवश्यकता है साथ ही इन स्टेशनों के प्लेटफार्मों के विस्तारीकरण की भी आवश्यकता है ताकि इन प्लेटफार्मों पर 24 कोच वाली लम्बी ट्रेने भी आराम से लग पाये परन्तु रेल बजट में ऐसे स्टेशनों पर यात्री सुविधा विकसित करने का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। हालाँकि उन्होंने बिहार के कुछ B क्लास स्टेशनों को ''आदर्श स्टेशन'' के रूप में विकसित करने की बजटीय घोषणा का स्वागत किया।

उन्होंने आगे कहा कि रेलगाड़ियों की संख्या बढ़ जाने के कारण दानापुर रेल मंडल पर अत्यधिक दबाब आ गया है। ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि इस मंडल में रेल ट्राफिक को सुविधाजनक बनाने के लिए रेल पटरियों का संख्या पर्याप्त रूप से बढ़ाई जायेगी किन्तु दुर्भाग्यवश, रेल बजट इस पर भी मौन है। चैम्बर अध्यक्ष ने रेल सुरक्षा एवं आधुनीकिकरण पर विशेष ध्यान दिये जाने के लिए इस बजट की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह अत्यन्त यथार्थ एवं सामयिक निर्णय है। उन्होंने बजट में बिहार को कुछ नई ट्रेने यथा छपरा-मडुआडीह इन्टसिटी, सिकन्दराबाद-दरभंगा एक्सप्रेस, रक्सौल-हावड़ा एक्सप्रेस, जयनगर-कोलकाता एक्सप्रेस, छपरा-लखनउ एक्सप्रेस हेतु बजट का स्वागत किया और आशा व्यक्त की है कि पूर्व के अनुभवों के विपरीत इस बार रेल प्रशासन इन बजटीय घोषणाओं का क्रियान्वयन समय पर करेगा।

राज्य में बिजली होगी और महंगी

ऐसे बढ़ी दरें: घरेलू उपभोक्ता

यूनिट	मौजूदादर	अनुमानित
1-100	2.50 रु०	2.65 - 2.75
101-200	3.10 रु०	3.25 - 3.40
201-300	3.75 रु०	4.00 - 4.10
300 से अधिक	4.70 रु०	5.00 - 5.20

बढ़ी दरें पहली अप्रैल से लागू करने की तैयारी *(साभार:हिन्दुस्तान,19.03.2012)*

पटना सिटी से फतुहा स्थानांतरित होंगे लघु उद्योग

पटना सिटी के आवसीय क्षेत्र में चल रहे लघु और कुटीर उद्योगों को फतुहा स्थानांतरित किया जायेगा। यह जानकारी उद्योग मंत्री रेणु कुमारी ने विधानसभा में दी। विधानसभा में अमरेंद्र प्रताप सिंह के सवाल के जवाब में रेणु कुमारी ने कहा कि इसके लिए फतुहा में 25 एकड़ भूमि चिह्नित की गयी है। बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (बियाडा) को जमीन का दाखिल-कब्जा कराने की कार्रवाई चल रही है। इसके बाद उद्योगों को स्थानांतरित कर दिया जायेगा। अमरेंद्र प्रताप सिंह ने पूछा था कि पटना सिटी की घनी आबादी से लघु व कुटीर उद्योगों को कहीं और स्थानांतरित करने के लिए क्या किया जा रहा है। *(साभार:प्रभातखबर,13.03.2012)*

जीएसटी को दो साल की छुट्टी !

प्रस्तावित नई वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) प्रणाली की राह आसान होती नहीं दिख रही है। इसे लागू करने की तय अवधि में तीन साल की देरी पहले ही हो चुकी है। हालाँकि ज्यादातर राज्य सरकारों का कहना है कि 2014 में आम चुनाव के कारण निकट भविष्य में इसके लागू होने की संभावना कम ही है।

गैर-कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों का तो यहाँ तक कहना है कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) के मौजूदा कार्यकाल में तो जीएसटी लागू नहीं ही होगा। उधर, वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने भी कहा कि जीएसटी जरूर आएगा लेकिन अभी इसे लागू करने के लिए राजनीतिक हालात सही नहीं हैं। एक संवाददाता सम्मेलन में मुखर्जी ने कहा, 'यह ऐसा कदम है, जिसके लिए संवैधानिक संशोधन की जरूरत है। इसके लिए संसद में दो-तिहाई बहुमत की दरकार है।'

संप्रग के वरिष्ठ मंत्रियों ने सभी कांग्रेसी और गैर कांग्रेसी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कहा है कि केंद्र जीएसटी जैसी अन्य बड़े मसलों पर फैसला 2014 के आम चुनाव के बाद ही किया जाएगा।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) शासित एक राज्य के वित्त मंत्री ने बताया, 'संप्रग के नेताओं का कहना है कि बड़े नीतिगत आर्थिक सुधार कार्यकाल के पहले याह दूसरे साल में ही लागू हो जाने चाहिए थे। 2013-14 में आम चुनाव होने हैं, तो केंद्र जीएसटी लागू नहीं करेगा क्योंकि इसे पूरी तरह लागू होने में ही दो साल का समय लगेगा। कार्यकाल के आखिरी साल में जीएसटी लागू करने से लोग खफा हो सकते हैं, जिसका असर आम चुनावों में कांग्रेस के प्रदर्शन पर पड़ सकता है।' राज्य सरकारों की चिंता यह है कि उन्हें पहले से ही भारी घाटा हो रहा था और केंद्र ने उन्हें कोई मुआवजा भी नहीं दिया है। केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष के बजट में केंद्रीय बिक्री कर (सीएसटी) की क्षतिपूर्ति के लिए राज्यों को महज 300 करोड़ रुपये आवंटित किए थे। केंद्र ने दो टूक लहजे में कह दिया है कि 2011-12 के लिए राज्यों को कोई मुआवजा नहीं मिलेगा और इसलिए सीएसटी मुआवजे पर 2012-13 के बजट में भी कुछ नहीं कहा गया है।

बिहार के वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा, 'समस्या यह है कि केंद्र सरकार ने बजट में जीएसटी लागू करने के बारे में कोई समयसीमा को घोषणा नहीं की है। पहले केंद्र ने कहा था कि जीएसटी 2011 में लागू होगा, इसके बाद इसे 2012 किया गया। लेकिन इस बार के बजट में जीएसटी पर बिल्कुल चुप्पी साध ली गई है। अब क्योंकि आम चुनाव नजदीक हैं और सरकार के लिए चुनाव से ठीक पहले जीएसटी जैसे अहम सुधार पर फैसला करना मुश्किल होगा। ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार जीएसटी लागू करने के लिए गंभीर नहीं है।'

मोदी ने कहा कि केंद्र ने सीएसटी की दरें 4 से घटाकर 2 फीसदी कर दी हैं और इससे राज्यों को हाने वाले घाटे की भरपाई करने के लिए उसने कोई आश्वासन नहीं दिया है। मोदी ने कहा, 'राज्यों ने 2010-11 के लिए 19,000 करोड़ रुपये के दावे किए थे लेकिन महज 6,000 करोड़ रुपये ही आवंटित किए गए। 2011-12 और 2012-13 के लिए भी कोई प्रावधान नहीं किया गया है। यह बेहद गंभीर मसला है और इस पर चर्चा के लिए मैं अधिकार प्राप्त समिति की बैठक बुलाऊँगा।' हालाँकि महज भाजपा शासित राज्य ही चिंतित नहीं हैं, कांग्रेस शासित राज्य भी ऐसी ही आशंकाओं से चिंतित हैं। हरियाणा की उत्पाद एवं कराधान मंत्री किरण चौधरी कहती हैं 'जीएसटी लागू करने से कर चोरी घटेगी और लालफीताशाही पर भी लगाम कसेगी। सबसे बड़ी चिंता इसे लागू करने में हो रही देरी है। सीएसटी में कटौती से राज्य के राजस्व को 2011-12 में करीब 3,000 करोड़ रुपये की चपत लगी है।' मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री राघवजी ने कहा, 'हमें नहीं लगता कि जीएसटी निकट भविष्य में लागू होने वाला है।'

(साभार:बिजनेसस्टैंडर्ड,20.03.2012)

टैक्स घटने पर भी नहीं मिल रहा लोगों को फायदा

वैट एक नजर में

वस्तु	पहले	वर्त्तमानदर
खाद्यान्न सामग्री (गेहूं, चावल)	4 प्रतिशत	1 प्रतिशत
मिठाई	12.5 प्रतिशत	कर-मुक्त (शून्य)
ड्राई फ्रूट्स	12.5 प्रतिशत	4 प्रतिशत
नमकीन	12.5 प्रतिशत	4 प्रतिशत
आलू-प्याज	4 प्रतिशत	कर-मुक्त (शून्य)
ऑटो-पार्ट्स	12.5 प्रतिशत	4 प्रतिशत

विस्तृतसमाचार:हिन्दुस्तान,12.03.2012)

लीज की जमीन बेची तो आधा फायदा निगम को

पटना क्षेत्रीय विकास प्राधिकार (विघटित) और पटना नगर निगम से लीज पर ली गयी संपत्तियों को बेचने पर मुनाफा का आधा हिस्सा निगम के खाते में जमा करना होगा। प्लांट, भवन, दुकान और फ्लैट समेत सभी तरह की ऐसी संपत्तियों पर यह निगम लागू होगा, जो लीज पर दी गयी है।

नगर आयुक्त पंकज कुमार पाल के प्रस्ताव पर निगम की सशक्त स्थायी समिति ने इसकी स्वीकृति दे दी है। अब तक लीज पर मिली संपत्ति को बेचने के मामले में लोग मनमानी करते थे। इसके कारण पटना नगर निगम और प्राधिकार को काफी घाटा हो रहा था।

निगम प्रशासन का कहना है कि लीज पर ली गयी संपत्तियों पर नाम ट्रांसफर करने के मुद्दे को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। पहले लीज के कुछ मामलों में बिना आधा मुनाफा लिए ही आवंटी को बेचने की अनुमति दे दी गई थी। साथ ही, नाम भी ट्रांसफर कर दिया गया है। जबकि कुछ मामलों में मुनाफा लेकर यह प्रक्रिया अपनायी गई है। यानी पदाधिकारियों की जैसी मर्जी, वैसा काम। इसका फायदा उठाकर कुछ आवंटियों ने बिना अनुमति लिए ही प्राधिकार से लीज पर ली गई संपति बेच दी है। प्रक्रियाओं में एकरूपता नहीं रखने के कारण प्राधिकार को आर्थिक क्षति हुई है।

ऑडिट रिपोर्ट में भी इस मामले पर सवाल उठाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक, इस मनमानी की वजह से अब तक 1.42 करोड़ रुपए का घाटा हो चुका है।

(विस्तृतसमाचार:हिन्दुस्तान,13.03.2012)

प्रॉपर्टी रजिस्ट्री करानी है तो अब देर न करें, एक अप्रैल से बढ़ेगा एमवीआर

बेतहाशा बढ़ी हैं कीमतें

राजधानी के आसपास के ग्रामीण इलाकों में प्रॉपर्टी की कीमतों में वृद्धि को देखते हुए इन इलाकों के एमवीआर में सौ फीसदी वृद्धि का प्रस्ताव है। हाल में इन इलाकों में सड़क समेत अन्य आधारभूत संरचनाओं का तेजी से विकास हुआ है। जो इलाके इससे प्रभावित होंगे, उनमें बैरिया, सोना गोपालपुर, चिपुरा, उदैनी, ढाली, फतेहपुर, लखना, भुसौला दानापुर, कुर्जी मोहम्मदपुर, शेखपुरा, फुलवारी शरीफ, नौबतपुर, बिहटा बख्तियारपुर आदि शामिल हैं।

एमवीआर निर्धारण

एमवीआर (मिनिमम वैल्यू रजिस्टर) वह दर है, जिसके हिसाब से सरकार रजिस्ट्री फीस वसूलती है। एमवीआर के निर्धारण का आधार संबधित इलाके में पिछले वित्तीय वर्ष में निबंधति हुए पांच उच्चतम मूल्य के दस्तावेजों का औसत है। जिन इलाकों में यह आंकड़ा उपलब्ध नहीं होता, वहां स्थल निरीक्षण कर एमवीआर तैयार किया जाता है।

पांच श्रेणी में बंटी है राजधानी

पांचवीश्रेणी फ्रेजर रोड, एग्जीबिशन रोड, एसपी वर्मा व भट्टाचार्या रोड, बेली रोड पर आयकर गोलबंर तक, तारामंडल से जीपीओ गोलंबर, बॉरिंग रोड, बोरिंग कैनाल रोड, गांधी मैदान के चारों तरफ के इलाके।

चौथीश्रेणी नाला रोड, आर्य कुमार रोड, बारी पथ, गोविंद मित्र रोड, खजांची रोड, खेतान मार्केट, हथुआ मार्केट, किदवईपुरी और श्रीकृष्णपुरी के इलाके।

तीसरीश्रेणी कंकड़बाग (पुराना बाइपास रोड), रमना रोड, कुनकुन सिंह लेन, शालीमार स्वीट्स व राजेंद्रनगर के कुछ इलाके।

दूसरीश्रेणी कंकड़बाग व राजेंद्रनगर का बचा क्षेत्र कांग्रेस मैदान, जगतनारायण रोड, बुद्धा कॉलोनी के इलाके।

पहलीश्रेणी जो इलाके इस सूची में नही है उन्हें पहली श्रेणी में रखा गया है।

शहरी क्षेत्र की दरें

जोन	वर्त्तमानदर	संभावितदर
जोन-1	650 - 1600	850 - 1800
जोन-2	1100 - 1800	1300 - 2000
जोन-3	1300 - 2200	1500 - 2400
जोन-4	1500 - 2300	1700 - 2500
जोन-5	1600 - 2700	1800 - 2900

(दरें अनुमानित प्रति वर्ग फीट रुपये में) (विस्तृतसमाचार:हिन्दुस्तान:19.03.2012)

एग्रो हब बन सकता है बिहार

राज्यसभा सांसद एनके सिंह ने कहा कि बिहार एग्रो प्रोसेसिंग हब बन सकता है। बिहार में फसलों व फलों का काफी अच्छा उत्पादन होता है। बिहार को विषेश राज्य का दर्जा मिलना ही चाहिए। विकास के लिए बिहार को प्रति वर्ष 25000 करोड़ मिलने चाहिए। होटल मौर्य में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत आने पर जापान के प्रधानमंत्री के किसी एक मुख्यमंत्री से मिलने की इचछा जतायी, उसमें उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चुना। जापान के प्रधानमंत्री ने कहा कि चीन और अन्य देशों के साथ मिल कर बिहार के बुद्धिस्ट टूरिज्म सर्किट बनवायेगा। एग्रो प्रोसेसिंग के क्षेत्र में भी पूंजी निवेश की इच्छा जतायी है।

पहलकरें मित्तल: उन्होंने सुनील भारती मित्तल से भी बिहार में उद्योग लगाने की अपील की। उन्होंने कहा कि बिहार ज्ञान का केंद्र रहा है। श्री सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार पूर्वी भारत से हरित क्रांति की अपेक्षा कर रहा है, लेकिन इसके लिए बजट में राशि 400 से बढ़ा कर मात्र एक हजार करोड़ की गयी है। इतनी कम राशि का प्रावधान किया जाना हास्यास्पद है। झारखंड के अलग होने के बाद बिहार को पर्याप्त सहायता राशि नहीं मिल सकी है। बिहार को आवश्यक सहायता राशि मिले, ताकि पर्याप्त विकास कार्य पूरा किया जा सके।

शिक्षा में बेहतर काम - रुक्मिणी: प्रथम की निदेशक रुक्मिणी बनर्जी ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में बिहार में पिछले कुछ वर्षों से बेहतर कार्य हुए हैं। बिहार में साक्षरता दर बढ़ी है। शिक्षा के विकास के लिए बिहार ने अपनी अलग रणनीति बनायी। राज्य में मिडिल और हाइस्कूल की संख्या और बढ़ानी होगी। उन्होंने कहा, शिक्षा के मामले में यूपी भी बिहार मॉडल अपनाना चाहता है। इसके लिए पिछले दिन यूपी के एक अधिकारी ने फोन कर इस संबंध में जानकारी मांगी थी। अक्षर आंचल और साक्षर भारत कार्यक्रम से साक्षरता दर में वृद्धि हुई है। अंक पहचानने में मोबाइल फोन ने भी अहम भूमिका निभायी है। मोबाइल के माध्यम से लोग समाचार सहित अन्य जानकारियाँ हासिल कर रहे हैं। बिहार में काफी संख्या में स्कूल भवन बन गये हैं। शिक्षक और पुस्तक भी उपलब्ध हैं। बच्चों के लिए बेसिक पढ़ाई की व्यवस्था की गयी है। पांच वर्षों में बिहार में शिक्षा की नींव और मजबूत होगी। नव साक्षरों की परीक्षा में जहाँ बिहार में 26 लाख लोगों ने परीक्षा दी, वही यूपी में मात्र छह लाख ही शामिल हुए। अब स्थिति यह है कि बिहार की लड़की पंजाब में भी टॉप कर रही है। शिक्षा के साथ कौशल विकास के लिए काम होगा। इसके लिए मिल कर काम करना होगा। मां और बच्चों को शिक्षित करना चुनौती है।

(साभार:प्रभातखबर,20.03.2012)

खेसारी से प्रतिबंध हटा, अब कर सकेंगे व्यापार

राज्य कैबिनेट में हुए खेसारी पर प्रतिबंध हटाने के फैसले से राज्य में दाल की कमी को पूरा किया जा सकेगा। साथ ही खेसारी की दाल अब गरीबों की थाली में दिखने लगेगी। खेसारी के व्यवसाय पर देश भर में प्रतिबंध लगभग 30 साल पहले लगाया गया था। उस समय की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि इस दाल के खाने से लकवा की बीमारी होती है। लेकिन उसके बाद कई रिपोर्टों में इस तर्क की निराधार बाताया गया। लिहाजा कई राज्यों ने खेसारी पर से प्रतिबंध हटा लिया लेकिन राज्य में यह अब भी जारी था।

(साभार:हिन्दुस्तान,7.3.2012)

INCOME GROWTH IN TIME WRAP

PERIODIC TABLE

Year	National per capita income	State per capita income	Bihar per capita income as percentage of national per capita income
2004-05	24143	7914	32.7
2005-06	26025	7813	30.0
2006-07	28083	9150	32.6
2007-08	30354	9685	31.9
2008-09	31801	10994	34.1
2009-10	33843	12012	35.5
2010-11	35993	13632	37.8
2011-12	38005	15268	40.1

(Source : The Telegraph, 27.03.2012)

Casual Workers

The Central Government had launched" Casual Labourers (Grant of Temporary Status and Regularization) Scheme of Government of India, 1993" for casual workers engaged by various Ministries / Departments and their attached and subordinate offices for work of casual or seasonal or intermittent nature. As per the scheme, Temporary status would be conferred to all casual labourers who were in employment and have rendered a continuous service of at least one year, which means that they must have been engaged for a period of at least 240 days (206 days in case of offices observing 5 days week) and would entitle the following benefits :

1. Wages at daily rates with reference to minimum of the pay scale for a corresponding group 'D' official including DA, HRA and CCA.
2. Benefits of increment at the same rate as applicable to a Group 'D' employee would be taken into account for calculating pro-rata wages for every one year of service.
3. Leave entitlement will be on a pro-rata basis at the rate of one day for every 10 days of work, casual or any kind of leave, except maternity leave, will not be admissible.
4. Maternity leave to lady casual labourers as admissible to regular Group 'D' employees will be allowed.
5. 50% of the service rendered under temporary status would be counted for the purpose of retirement benefits after their regularization.
6. After rendering three years' continuous service after conferment of temporary status, the casual labourers would be treated on par with temporary Group 'D' employees for the purpose of contribution to the General Provident Fund, and would also further be eligible for the grant of Festive Advance/Food Advance on the same conditions as are applicable to temporary Group 'D' employees.
7. Until they are regularized, they would be entitled to productivity Linked Bonus/Ad-hoc bonus only at the rates as applicable to casual labourers.

(Source : AIOE News, January, 2012)

Economically active children in India (Age 5-14 years)

Year	Number of working Children
1981 (Census)	1.30 crore
1991 (Census)	1.13 crore
2001 (Census)	*1.26 crore
2004-05 (NSSO)	90.75 lakh
2009-10 (NSSO)	49.84 lakh

(Source : AIOE News, February 2012)

Statement about ownership and other particulars about newspaper of the Bihar Chamber of Commerce Fortnightly Bulletin to be published in the first issue every year after last day of February.

श्वतउ . प्ट
ेमम त्नसम ठख्र

1. Place of Publication : The Bihar Chamber of Commerce, Khem Chand Chaudhary Marg, Patna - 800 001
2. Periodicity of its publication : Fortnightly
3. Printer's Name : Eqbal Siddiqui
   Whether Citizen of India? : Indian
   (If foreigner, state the Country of origin)
   Address : Additional Secretary The Bihar Chamber of Commerce, Khem Chand Chaudhary Marg, Patna-800 0001
4. Publisher's Name : Eqbal Siddiqui
   Whether Citizen of India? : Indian
   (If foreigner, state the Country of origin)
   Address : Additional Secretary, The Bihar Chamber of Commerce, Khem Chand Chaudhary Marg, Patna-800 0001
5. Editor's Name : Shri Sanjay Kr. Khemka
   Whether Citizen of India? : Indian
   (If foreigner, state the Country of origin)
   Address : Commercial Steel Engg. Corporation 13/1, Industrial Estate, Patliputra, Patna - 800 013
6. Name and Address of Individual who own the newspaper and parterns of share holders : The Bihar Chamber of Commerce, Khem Chand Chaudhary Marg, Patna-800 0001

I, Eqbal Siddiqui, hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

(Eqbal Siddiqui)
Publisher

अनुरोध चैम्बर कार्यालय द्वारा मेम्बरशिप लिस्ट अपडेट किया जा रहा है। माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने कार्यालय, आवास, फैक्स, मोबाईल नम्बर एवं ई-मेल आईडी की जानकारी चैम्बर कार्यालय में भेजने की कृपा करें। चैम्बर के ई-मेल **bccpatna@gmail.com** पर भी सदस्य उक्त जानकारी दे

EDITORIAL BOARD

Editor
Sanjay Kumar Khemka
Secretary General

K. P. Singh
Chairman
Library & Bulletin Sub-Committee

Printer & Publisher
Eqbal Siddiqui
Addl. Secretary

Khemchand Chaudhary Marg, Patna - 800 001 • Ph. 0612-3200646, 2677605, 2677635, Fax No. : 0612-2677505, E-mail : bccpatna@gmail.com

Price Rs. 0.25

Design & Printed by : Sharada Enterprises, Patna, Ph.:0612-2690803, 2667296